The economic Times. (Hindi.) 28-6-13.

नए शुगर PDS पर नॉर्थ-ईस्ट की PM से फरियाद

नया राशनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए और वक्त मांग रहे राज्य

[ईटी ब्यूरो गुवाहाटी & नई दिल्ली]

नॉर्थईस्ट राज्यों में नए शुगर राशनिंग प्रोग्राम का लॉन्च टालने में नाकाम रहने के बाद अब ये राज्य इसमें प्रधानमंत्री के दखल की मांग कर रहे हैं। इन आठ राज्यों की आस अब प्रधानमंत्री पर टिकी है, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री न्यू शुगर राशनिंग सिस्टम को लागू करने में मदद देने को तैयार नहीं है। इस प्रोग्राम के तहत राज्यों को ओपन मार्केट से शुगर खरीदकर इसे सब्सिडी पर बेचना होगा। जुलाई से केंद्र सरकार राशन दुकानों के लिए चीनी मिलों से शुगर नहीं खरीदेगी। राज्यों को टेंडरिंग के जरिए चीनी ओपन मार्केट से खरीदनी होगी और इसे राशन दुकानों पर सब्सिडी पर बेचना होगा। वहीं, केंद्र सरकार इस पर 18.50 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देगी।

त्रिपुरा सरकार में फूड सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स सेक्रेटरी और कमिश्नर बिजॉय कान्ति रॉय ने बताया, 'नॉर्थईस्ट के साथ लॉजिस्टिक्स की समस्या है। लिहाजा, यहां स्पेशल डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की जरूरत है। हमें केंद्र सरकार से और वक्त मिलने की उम्मीद है।'

ट्रांसपोर्ट की चुनौतियों का हवाला देते हुए मिजोरम सरकार ने केंद्र की तरफ से तय सब्सिडी पर सवाल उठाए हैं। फूड मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी में राज्य सरकार ने कम से कम प्रति किलो 25 रुपए सब्सिडी की मांग की है। असम के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हमारे मुख्यमंत्री ने पीएम को हालात से वाकिफ करा दिया है। नियमों में ढील की हमारी मांग पर अब तक केंद्र का जवाब नहीं आया है।'

हालांकि, फूड मिनिस्ट्री ऐसे मांगें मानने के मूड में नहीं है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्ट्री के अधिकारी ने बताया, 'पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के तहत शुगर की खरीद, स्टोरेज और बिक्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सभी राज्यों को वक्त दिया गया।' स्टोरेज की समस्या से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए फूड मिनिस्ट्री प्राइवेट मिलों से बात कर रही है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग असम में कॉरपोरेशन बनाने पर विचार कर रहा है, जो राज्य के लिए शुगर खरीदेगा। उन्होंने कहा, 'चीजें रातोंरात नहीं होती हैं। हमें सिस्टम बनाने के लिए वक्त चाहिए।'

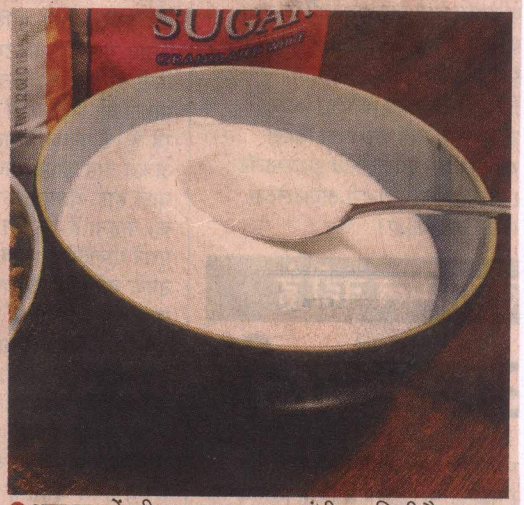

- **आठ राज्यों** की आस अब प्रधानमंत्री पर टिकी है, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री न्यू शुगर राशनिंग सिस्टम को लागू करने में मदद देने को तैयार नहीं है
- न्यू शुगर राशनिंग सिस्टम के तहत राज्यों को ओपन मार्केट से शुगर खरीदकर इसे सब्सिडी पर बेचना होगा। जुलाई से केंद्र सरकार राशन दुकानों के लिए चीनी मिलों से शुगर नहीं खरीदेगी